

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान दिल्ली की 1500 से अधिक अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 30 लाख से अधिक गरीब एवं निम्न मध्यम श्रेणी के नागरिकों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली की कुल आबादी का पांचवां भाग बुनियादी नागरिक सुविधाओं के अभाव में और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता की स्थिति में जी रहा है। इस दयनीय स्थिति से 30 लाख नागरिकों को मुक्ति दिलाना सरकार का नैतिक एवं मानवीय दायित्व तो है ही, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व भी है। मेरा सम्मानित सदन एवं सरकार से आग्रह है कि निर्वाचित विधान सभा द्वारा दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों को, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में घोषित वर्ष 1976-77 की नियम नीति के आधार पर, नियमित करने के तर्कसंगत एवं लोक स्वीकार्य सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार किया जाये और नियमन प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये।